केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा संस्तुत जातियां

2422. **प्रो॰ रामगोपाल यादवः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य-वार कितनी जातियों उप-जातियों और उनके पर्यायों को पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) सिफारिश की गई जातियों में से कितनी जातियों को सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है;

(ग) या सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक आयोग की कितनी सिफारिशों का अनुपालन किया गया है और तद्नुसार उसका क्या परिणाम रहा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) विवरण संलग्न है (नीचे देखिये)।

(ख) पिछड़े वर्गों के रूप में 6 जातियां/उप जातियां/पर्याय अधिसूचित की गई।

(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत, आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतः केन्द्र सरकार पर बाध्य होगी।

(घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तीन सलाहों को उत्तर प्रदेश की पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के दौरान पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा संस्तुत जातियों/उप जातियों/पर्यायों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	चंडीगढ़	5
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7
4.	गोवा	3
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	14
7.	कर्नाटक	94
8.	केरल	17
9.	मध्य प्रदेश	23
10.	महाराष्ट्र	19
11.	उड़ीसा	16
12.	पंजाब	6
13.	राजस्थान	19
14.	सिक्किम	1
15.	तमिलनाडु	13
16.	उत्तर प्रदेश	25
17.	पश्चिम बंगाल	15

Experiment on Animals in Research Institutes

2423. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI P. PRABHAKAR REDDY:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government have decided to control/regulate experiments on animals in the research institutions/biomedical research in the country as reported in the Hindustan Times dated the 16th November, 1998;

(b) whether Government have set up any advisory Committee in this regard; if so, what were the recommendations made by it; and

(c) what is Government's reaction to the suggestions/amendments in this regard made by the Director, Centre for